

2018-19 सीज़न की रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 2018-19 सीज़न की सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि किसान अनुकूल इस पहल से किसानों को 62,635 करोड़ रुपए का अतिरिक्त रटिर्न मिलागा। इस पहल के तहत अधिसूचित फसलों की एमएसपी बढ़ाते हुए उत्पादन लागत पर कम-से-कम 50 प्रतिशत रटिर्न सुनिश्चित किया गया है।
- गेहूँ की एमएसपी में प्रति क्वटिल 105 रुपए, कुसुम की एमएसपी में प्रति क्वटिल 845 रुपए, जौ की एमएसपी में प्रति क्वटिल 30 रुपए, मसूर की एमएसपी में प्रति क्वटिल 225 रुपए, चने की एमएसपी में प्रति क्वटिल 220 रुपए तथा रेपसीड एवं सरसों की एमएसपी में प्रति क्वटिल 200 रुपए की वृद्धि की गई है जो इस दशा में एक और प्रमुख कदम है।
- गेहूँ, जौ, चना, मसूर, रेपसीड एवं सरसों और कुसुम के लिये सरकार द्वारा तय की गई एमएसपी उत्पादन लागत के मुकाबले काफी अधिक है। गेहूँ की उत्पादन लागत 866 रुपए प्रति क्वटिल और एमएसपी 1840 रुपए प्रति क्वटिल है, जो उत्पादन लागत की तुलना में 112.5 प्रतिशत का रटिर्न देती है।
- जौ की उत्पादन लागत 860 रुपए प्रति क्वटिल और एमएसपी 1440 रुपए प्रति क्वटिल है, जो 67.4 प्रतिशत का रटिर्न देती है। चने की उत्पादन लागत 2637 रुपए प्रति क्वटिल और एमएसपी 4620 रुपए प्रति क्वटिल है, जो 75.2 प्रतिशत का रटिर्न सुनिश्चित करती है।
- मसूर की उत्पादन लागत 2532 रुपए प्रति क्वटिल और एमएसपी 4475 रुपए प्रति क्वटिल है, जो 76.7 प्रतिशत का रटिर्न देती है। रेपसीड एवं सरसों की उत्पादन लागत 2212 रुपए प्रति क्वटिल और एमएसपी 4200 रुपए प्रति क्वटिल है, जो 89.9 प्रतिशत का रटिर्न सुनिश्चित करती है। कुसुम की उत्पादन लागत 3294 रुपए प्रति क्वटिल और एमएसपी 4945 रुपए प्रति क्वटिल है, जो 50.1 प्रतिशत का रटिर्न देती है।

2019-20 सीज़न में वपिणन की जाने वाली 2018-19 सीज़न की सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का उल्लेख निम्नलिखित है:-

फसल	एमएसपी 2017-18 (रुपए प्रति क्वटिल)	एमएसपी 2018-19 (रुपए प्रति क्वटिल)	उत्पादन लागत 2018-19 (रुपए प्रति क्वटिल)	एमएसपी में वृद्धि शुद्ध अंतर %	लागत* की तुलना में रटिर्न (प्रतिशत में)
गेहूँ	1735	1840	866	105	6.1
जौ	1410	1440	860	30	2.1
चना	4400	4620	2637	220	5.0
मसूर	4250	4475	2532	225	5.3
रेपसीड एवं सरसों	4000	4200	2212	200	5.0
कुसुम	4100	4945	3294	845	20.6

*इसमें अदा की गई समस्त लागत शामिल है जैसे कि मज़दूरों पर खर्च की गई धनराशि, बैल/मशीन पर खर्च की गई रकम, पट्टे पर ली गई भूमि के लिये अदा की गई मालगुजारी, कच्चे माल पर खर्च की गई धनराशि आदि।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)

- सरकार द्वारा इस नई समग्र योजना की घोषणा करने के परिणामस्वरूप अब एक ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था उपलब्ध हो गई है, जिससे अब किसानों को एमएसपी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी।
- इस समग्र योजना में तीन उप-योजनाएँ यथा- मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य अंतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और नज़ी खरीद एवं स्टॉकसिंट योजना (पीपीएसएस) शामिल हैं, जिन्हें प्रायोगिक (पायलट) आधार पर शुरू किया गया है।
- इस योजना के तहत सरकार ने 16,550 करोड़ रुपए की अतिरिक्त गारंटी देने का निर्णय लिया है जिसके फलस्वरूप कुल सरकारी गारंटी अब 45,550 करोड़ रुपए हो गई है। इसके अलावा, उपज खरीद परिचालन के लिये बजट प्रावधान भी बढ़ा दिया गया है और पीएम-आशा के कार्यान्वयन के लिये

15,053 करोड़ रुपए मंजूर किये गए हैं।

- केंद्र एवं राज्यों की खरीद एजेंसियों जैसे कि भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी वपिणन संघ लिमिटेड, छोटे किसान कृषि कारोबार कंसोर्टियम आगे भी रबी फसलों के लिये किसानों को मूल्य संबंधी समर्थन प्रदान करते रहेंगे।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cabinet-approves-enhanced-msp-for-rabi-crops-of-2018-19-season>

